www.tamsasanket.com
वर्षः 05 || अंक 303 || लखनऊ
शुक्रवार
06 फ़रवरी 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
75 आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

मौसम
सूर्योदयः 6:49
सूर्यास्तः 05:52
अधिकतमः 22°00
न्यूनतमः 11°00

पेज 03

विशेष समाचार | एक 'ऐतिहासिक सफलता' यां ... >> पेज 02 | यूपी में चाइनीज मांझे से मौत अब ... >> पेज 04 | 50 साल के हुए अभिषेक ...

कांग्रेस के वक्त डील यानी बोफोर्स घोटाला : मोदी

ये मोहब्बत की दुकान मोदी की कब्र खोदने की बात करती है, विपक्ष का वॉकआउट

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। स्पीच के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़गेजी की उम्र देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाजत दी जाए। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री ने एक घंटा 27 मिनट भाषण दिया। मोदी ने कहा कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, जो मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का अपमान नहीं है। PM बोले- टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, डीएमके दशकों से केंद्र में सत्ता का हिस्सा रहे। उनकी पहचान क्या बनी, उनके वक्त डील के नाम पर बोफोर्स याद आता है। आज डील की चर्चा गौरव से होती है प्रधानमंत्री मोदी को बुधवार शाम 5 बजे लोकसभा में भी स्पीच देनी थी, लेकिन विपक्ष के विरोध चलते स्पीकर ओम बिरला ने भाषण टाल दिया। स्पीकर ने कहा कि सदन में पीएम के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। ये सांसद मंगलवार को हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन का विरोध कर रही थीं। हंगामे के चलते स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। कुछ मंत्रियों ने विपक्षी सांसदों से जाने को कहा, इसके बाद उन्होंने घेराव बंद किया। PM ने कहा कि इंदिरा गांधी जिस प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ा रही थीं, उसके जन्मदाता उनके पिताजी थे 2014 से पहले सब दुखी थे। सब गलती देख रहे थे।

>> (शेष पेज 04 पर)

पीएम ने कहा- 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट

PM ने कहा कि इनकी सरकार रिमोट से चलती थी। मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है, लेकिन 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट हैं। सत्ता हमारे लिए सुख नहीं सेवा का आसन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना लाखों करोड़ों का लोन दिया, स्वरोजगार को बल दिया।

स्पीकर बोले-कल पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था : ओम बिरला

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। इसलिए उनकी कल शाम 5 बजे होने वाली स्पीच टालनी पड़ी। आशंका के चलते मैंने ही उनसे न आने का आग्रह किया था। सूत्रों के हवाले से बताया है कि बुधवार को PM की स्पीच के दौरान कांग्रेस लोकसभा में उन पर हमला करने की योजना बना रही थी, दरअसल, पीएम मोदी 5 फरवरी को लोकसभा में शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे के चलते स्पीकर संध्या राय ने कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी।

पीएम की लोकसभा में स्पीच टाली गई थी

बुधवार शाम 5 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब विपक्ष की महिला सांसदों ने सत्ताधारी नेताओं की कुर्सियां घेर लीं। इनमें पीएम मोदी की कुर्सी भी थी। महिला सांसदों के हाथ में बड़े बैनर थे, जिन पर लिखा था- जो सही है, वो करो लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। 2004 के बाद पहली बार यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ है।

"पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया, कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। इन्होंने उनके पद का अपमान किया। गरीबी से निकली हुई एक महिला का अपमान किया। आपने आदिवासियों का अपमान किया है। पीएम ने कहा- अरुणाचल और असम को जोड़ने वाला ब्रिज कितने सालों तक लटका रहा है, उसे हमने पूरा किया। हमारी सोच है कि देशवासियों को भरोसा है हम पर कि कितनी भी चुनौतियां उनका हम समाधान कर सकते हैं।

लोकसभा में पीएम की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पास

बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। 2004 के बाद पहली बार यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ है। इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन PM मनमोहन सिंह को धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने दिया था। वहीं प्रधानमंत्री ने गुरुवार को राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 97 मिनट का भाषण दिया। विपक्षी सांसदों ने स्पीच की शुरुआत में यहां भी हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर गए। गुरुवार को लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की।

पीएम बोले- 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को पीछे छोड़ा

PM ने कहा कि आज 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को पीछे छोड़ा है। आज वे हमारे साथ चल रहे हैं। 2014 के पहले रेलवे क्रॉसिंग से स्कूल की बस जाती थीं, 20-20 बच्चों की मौत खबर आती थी। हमने सारे क्रॉसिंग बंद की इसलिए ये मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं।

पीएम बोले- 3 दिन धरने पर बैठा, तब सरदार सरोवर डैम बनाने की अनुमति मिली

PM ने कहा कि मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले सरदार वल्लभ भाई ने नर्मदा नदी पर बांध बनाने की कल्पना की। लेकिन इसका उद्घाटन मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया ये हाल था। सीएम रहते मैं 3 दिन धरने पर बैठा तब जाकर सरदार सरोवर डैम बनाने की अनुमति मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी को बुधवार शाम 5 बजे लोकसभा में भी स्पीच देनी थी, लेकिन विपक्ष के विरोध चलते स्पीकर ओम बिरला ने भाषण टाल दिया। स्पीकर ने कहा कि सदन में पीएम के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी।

मोदी की स्पीच की 5 बड़ी बातें...

*1. **कांग्रेस के पीएम के पास सोच नहीं थी:** लालकिले से दिए कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के भाषण का एनालिसिस कर लीजिए। इससे पता चल जाएगा कि उनके पास कोई विजन नहीं था। हमारी काफी ताकत उनकी गलतियों को सुधारने में लग रही है। उस दौर में दुनिया के मन में हमारी जो इमेज बनी थी, उसे मिटाने में बहुत मेहनत लगती है।*

*2. **देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है:** आज देश नीति के आधार पर चल रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम आगे बढ़ चले हैं। सच्चाई यह है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर विश्व से प्रतिस्पर्धा करने को तैयार है। MSME का नेटवर्क जितना बढ़ा है, दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।*

*3. **ईयू और अमेरिका से ट्रेड डील गर्व का विषय:** आज भारत अनेक देशों के साथ ट्रेड डील कर रहा है। पिछले कुछ समय में हमने दुनिया के 9 बड़े और महत्वपूर्ण देशों के साथ ट्रेड डील साइन की हैं। एकसाथ 27 देशों के साथ डील की हैं। इसमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से डील भी शामिल है। इनके (कांग्रेस) के समय डील बोफोर्स थी। आज डील गर्व का विषय है।*

*4. **नेहरू ने शुरुआत कराई, उद्घाटन किया:** कांग्रेस की इम्प्लीमेंट नीति की मिसाल देना चाहता हूं। गुजरात के लिए जब नर्मदा डैम की योजना बनाई गई, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सरदार पटेल के निधन के बाद नेहरूजी ने इसकी शुरुआत कराई। कमाल की बात है कि जब मैं प्रधानमंत्री बना, तब इसका उद्घाटन किया। मैंने सीएम रहते हुए इस डैम के लिए 3 दिन तक अनशन किया। किसानों के लिए मैंने अपने आपको दांव पर लगा दिया था।*

*5. **आज NPA 1% से नीचे:** 2014 से पहले नेता के फोन जाते थे और उनके आधार पर लोन देते थे। गरीब, बैंक के दरवाजे तक भी नहीं जा पातेथे। कांग्रेस राज में बैंकिंग सेक्टर तबाही के कगार पर था। मैं पीएम बना तो बैंकों को भरोसे में लिया। आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) 1% से भी नीचे है। बैंकों का प्रॉफिट रिकॉर्ड पर है।*

मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाका

कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

16 लोगो की मौत

हादसा

तमसा संकेत, एजेंसी

धमाके के समय खदान के अंदर कितने मजदूर थे, यह अभी साफ नहीं है।

शिलांग। मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को अवैध कोयला खदान में धमाका हो गया। हादसे में कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूरों के अब भी खदान में फंसे होने की आशंका है। यह जानकारी राज्य की पुलिस महानिदेशक आई. नोंग्रांग ने दी। बचाव दल राहत और खोज अभियान में लगे हुए हैं। यह हादसा सुबह थांग्स्कु इलाके में हुआ। पुलिस महानिदेशक ने कहा,अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं। धमाके के समय खदान के अंदर कितने मजदूर थे, यह अभी साफ नहीं है। और लोगों के फंसे होने की आशंका है। ईस्ट जैंतिया हिल्स के SP विकाश कुमार ने बताया कि एक घायल व्यक्ति को पहले सुतंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

>> (शेष पेज 04 पर)

यूपीएससी-सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने का रास्ता बंद

रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार, नए नियम 2026 से लागू

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन गुरूवार को जारी किया है। आयोग ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। परीक्षा केंद्र में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही एंट्री दी जाएगी। इस बार प्रयास और पात्रता से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक अब सिलेक्शन के बाद दोबारा परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं रहेगी। नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं, IAS और IFS को लेकर पुराने नियम जस के तस रखे गए हैं। चयनित अफसर को एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। जैसे किसी का 2026 में IPS में सिलेक्शन हुआ तो वह 2027 में परफॉर्मेंस बेहतर करने की परीक्षा देने का पात्र होगा। उसके बाद अगर वह परीक्षा देना चाहता है तो उसे सेवा से इस्तीफा देना होगा। पहले से आईपीएस में चयनित या नियुक्त उम्मीदवार सीएसई 2026 से दोबारा आईपीएस नहीं पा सकेंगे। वहीं प्रीलिम्स के बाद लेकिन मेन्स से पहले अगर आईएएस या आईएफएस बनते हैं, तो मेन्स लिखने की अनुमति नहीं मिलेगी। सिविल सर्विस एग्जाम-2026 में अगर ग्रुप-ए या फिर आईपीएस मिलती है।

>> (शेष पेज 04 पर)

फास्ट न्यूज

मणिपुर की नई डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन का विरोध

नई दिल्ली/इंफाल। मणिपुर में आज से विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद बुलाया गया है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने गुरुवार शाम 4 बजे से सत्र बुलाया है। इधर, दिल्ली में बुधवार शाम को कुकी-जो समूह से जुड़े लोगों ने मणिपुर भवन के बाहर प्रदर्शन किया।

तीन छात्राओं पर कटर हमला करने वाला साइको मैन गिरफ्तार

भोपाल। भोपाल में तीन छात्राओं पर कटर से हमला करने वाला साइको मैन, पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। उसे बुधवार रात छोला इलाके में घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी देवेंद्र अहिरवार सागर जिले का रहने वाला है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पत्नी से झगड़ा होने के बाद उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बाद एक तीन छात्राओं को निशाना बनाया। उसने इससे पहले सागर में भी चार युवतियों को कटर मारकर घायल किया था। भोपाल पुलिस ने उस पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।

हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम

शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलेगा। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार- 9 फरवरी को वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इससे 10 और 11 फरवरी को पूरे प्रदेश में बारिश बर्फबारी होगी। इससे पहले, 6 फरवरी को चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर की अधिक ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो सकता है।

बंगाल में 21-40 की उम्र के बेरोजगारों को ₹1500 मिलेंगे

कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा, 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश

बढ़ोतरी

तमसा संकेत, एजेंसी

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में राज्य का अंतरिम बजट पेश किया।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 21-40 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों को 1,500 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में दोबारा आती है ते यह योजना 15 अगस्त से शुरू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले में डियरनेस अलाउंस(DA) में भी 4% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत भी 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसमें अभी तक सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए और SC/ST महिलाओं को 1,200 रुपए दिए जाते थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। राज्य में तीन महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि केंद्र पर पश्चिम बंगाल का लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का वैध बकाया है। बनर्जी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें और सर्व शिक्षा अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं के लिए फंड सालों से रोक दिया गया है।

लखनऊ से गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा रवाना

डिप्टी सीएम ब्रजेश ने दिखाई हरी झंडी, बोले- अंतिम व्यक्ति तक हेल्थ सर्विस पहुंचे

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक गुणवत्तापरख स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से कार्य कर रही है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 के अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाए जाने के लिए चिकित्सकों का दल रवाना हो रहा है। यह स्वास्थ्य सेवा यात्रा भारत-नेपाल सीमा से सटे थारू बाहुल्य क्षेत्रों में जनसेवा का सशक्त माध्यम बन रही है। यह कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। डॉ.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवध और गोरक्ष प्रांत तथा श्रीगुरु गोरखनाथ सेवा न्यास द्वारा आयोजित गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा- यह स्वास्थ्य सेवा यात्रा भारत-नेपाल सीमा से सटे थारू बाहुल्य क्षेत्रों में जनसेवा का सशक्त माध्यम बन रही है। इसके अंतर्गत महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती एवं बहराइच जनपदों में निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के माध्यम से जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर चिकित्सकों को विश्व की सबसे छोटी ईसीजी मशीन "स्पंदन ईसीजी मशीन" का वितरण और थारू बाहुल्य जनपदों की ओर रवाना होने वाली बसों को झंडी दिखा कर रवाना भी किया गया। छह से आठ फरवरी तक संबंधित जिलों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे।

>> (शेष पेज 04 पर)

लखनऊ में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 को झंडी दिखाकर रवाना करते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।

7 जिलों में आयोजित होंगे कैम्प

गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास और नेशनल मेडिकोज़ आर्गेनाइजेशन अवध-गोरक्ष प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस यात्रा में इस वर्ष लगभग 70 मेडिकल संस्थानों से 700 चिकित्सक और मेडिकल छात्र भाग ले रहे हैं। NMO अवध प्रांत के सचिव डॉ शिवम मिश्र के अनुसार इस यात्रा में भारत नेपाल सीमा के थारू बहुल पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बहराइच के लगभग 300 स्थानों पर यह मेडिकल कैम्प आयोजित हो रहे हैं।

इस दौरान मंत्री दयाशंकर सिंह और असीम अरुण मौजूद रहे।

हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

उप मुख्यमंत्री ने थारू बाहुल्य जनपदों की ओर रवाना होने वाली बसों को झंडी दिखा कर रवाना भी किया। जिससे संगठित एवं सुचारु रूप से जनसेवा का यह अभियान धरातल पर पहुंचेगा। इस अवसर पर चिकित्सकों को विश्व की सबसे छोटी ईसीजी मशीन "स्पंदन ईसीजी मशीन" का वितरण भी किया गया। डिप्टी सीएम ने बताया कि यह मशीन बिना बैटरी और इंटरनेट के भी कार्य करने में सक्षम है। यह अत्याधुनिक तकनीक रिमोट एरिया में त्वरित व सटीक जांच को संभव बनाकर जनस्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाएगी। सेवा, समर्पण और नवाचार से जुड़ी यह पहल अंतिम पंक्ति तक स्वास्थ्य के संकल्प को सशक्त करती है।

'लापता लेडीज' की संख्या बढ़ी

लापता लोगों के मामलों में दिल्ली पुलिस का 77% रिकवरी रेट

तलाश

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लापता लोगों की संख्या को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से एक आंकड़ा जारी किया गया। पुलिस की ओर से बुधवार जारी इन आंकड़ों के अनुसार शहर में लापता लोगों की संख्या लगभग एक दशक से स्थिर बनी हुई है। 2016 से यह आंकड़ा प्रति वर्ष 23,000 से 24,000 के आसपास रहा है। तेजी से दिल्ली की बढ़ती आबादी के बावजूद कोई खास उछाल नहीं देखने को मिला है। पुलिस के अनुसार 2026 की शुरुआत में लापता लोगों की संख्या में गिरावट देखी गई है। पूर्व के आंकड़ों के अनुसार औसतन प्रति माह लगभग 2,000 लोग लापता होते हैं, वहीं इस साल जनवरी के महीने में 1,777 मामले दर्ज किए गए। 2016 से इन 2 हजार लापता लोगों में से दिल्ली पुलिस ने 1,80,805 लोगों का पता लगाकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाया है। रिकवरी रेट लगभग 77% है। इसका मतलब है कि लापता होने वाले प्रत्येक 10 में से लगभग 8 लोगों के मामलों को स्थानीय पुलिस सफलतापूर्वक सुलझा लेती है। पुलिस ने इसका श्रेय 'ऑपरेशन मिलाप' जैसी पहल को दिया, जो विशेष रूप से लापता बच्चों और वयस्कों को बचाने पर केंद्रित है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि दिल्ली पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए जिन उपायों को अपनाती है उसके बेहतर रिजल्ट सामने आए हैं। चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर और AI का इस्तेमाल पुलिस बल की सहायता कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से लापता बच्चों की बड़ी संख्या का पता लगाने वाले पुलिसकर्मियों को दिया जाने वाला असाधारण कार्य पुरस्कार भी अच्छे परिणाम दे रहा है। इस प्रकार का मामला दर्ज होते ही पुलिस टीमें उपलब्ध इनपुट के आधार पर लोगों का पता लगाने के लिए आश्रय गृहों, बस स्टैंडों और अन्य स्थानों का दौरा शुरू कर देती हैं लापता होने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। इस कैटेगरी में 2016 में 1,606 से बढ़कर 2025 में संख्या 5,576 हो गई है, जो तीन गुना से अधिक है।

>> (शेष पेज 04 पर)

रेलवे आरएसी बर्थ मिलने पर आंशिक किराया लौटाए: संसदीय समिति

नई दिल्ली। संसदीय समिति ने मंगलवार को कहा RAC कैटेगरी के तहत बुक किए गए टिकटों के लिए यात्री से पूरा किराया लेना सही नहीं है। समिति ने रेल मंत्रालय को सुझाव दिया कि रेल मंत्रालय को ऐसे यात्री को आंशिक किराया वापस करने के लिए नियम बनाना चाहिए। मौजूदा नियम के तहत, रेलवे RAC कैटेगरी के तहत ट्रेनों में बर्थ बुक करने के लिए यात्री से पूरा किराया लेता है। हालांकि, यात्री RAC कैटेगरी में रह सकता है और बर्थ दूसरे RAC यात्री के साथ साझा कर सकता है। दोनों यात्री रेलवे को पूरा किराया देते हैं। वहीं, सुपरफास्ट ट्रेनों को कैटेगराइज करने के लिए समिति ने कहा कि इसके लिए 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार का बेंचमार्क बेहद कम है। समिति ने कहा कि 2007 से सुपरफास्ट ट्रेनों के कैटेगराइजेशन के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी 55 किमी/घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनें सुपरफास्ट मानी जाती हैं।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील का जॉइंट स्टेटमेंट 4-5 दिन में आएगा

पीयूष गोयल बोले- मिड-मार्च तक पहला ट्रांच फाइनल होने की उम्मीद

तैयारी

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार (5 फरवरी) को कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बाइलेटरल ट्रेड डील पर जॉइंट स्टेटमेंट अगले 4-5 दिनों में फाइनल और साइन हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह डील का पहला ट्रांच है और इसका लीगल टेक्स्ट मिड-मार्च तक तैयार हो जाएगा। गोयल ने संसद में और मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। गोयल ने स्पष्ट किया कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को इस डील में फुली प्रोटेक्ट किया गया है। फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग में दोनों देशों के क्रिटिकल और सेंसिटिव सेक्टर सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इस डील में कोई इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट नहीं है। अमेरिका की तरफ से इंडियन गुड्स पर टैरिफ कम होने के बाद भारत भी अमेरिकी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर गुड्स पर टैरिफ जीरो करेगा। इसमें ट्री नट्स, वाइन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आदि शामिल हैं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर ने इसे बिग विन बताया। गोयल ने कहा कि इससे MSME, एंटरप्रेन्योर्स, स्किल्ड वर्कर्स और इंडस्ट्री को नए अवसर मिलेंगे।

"पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत तेजी से चल रही है। जॉइंट स्टेटमेंट साइन होने के बाद अमेरिका भारतीय गुड्स पर टैरिफ घटाकर 18% कर देगा। गोयल ने बताया कि यह वर्चुअल तरीके से भी साइन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका कॉम्प्लिमेंट्री इकोनॉमी हैं, यह डील दोनों के लिए फायदेमंद होगी।

>> (शेष पेज 04 पर)

C M Y K

एक 'ऐतिहासिक सफलता' यां 'राजनीतिक संकेत'

सम्पादकीय

इस्लामिक जगत में बदलते समीकरण

पश्चिम और दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना इस समय एक गहरे, लेकिन अपेक्षाकृत शांत परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसके मूल में विचारधारा से अधिक भू-राजनीतिक यथार्थ, आर्थिक गणनाएं और क्षेत्रीय शक्तियों की बढ़ती आत्मनिर्भरता है। अमेरिका की घटती सुरक्षा भूमिका, यूरोप की आंतरिक विभाजित स्थिति और वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलावों ने क्षेत्रीय देशों को अपनी सुरक्षा जिम्मेदारी स्वयं संभालने के लिए प्रेरित किया है। लंबे समय तक पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकी नेतृत्व और गारंटी पर आधारित रही, किंतु ट्रंप के कार्यकाल के बाद से अमेरिका की नीति अधिक लेन-देन आधारित और अनिश्चित होती गई है। इससे पारंपरिक सहयोगी देशों को यह महसूस होने लगा कि संकट के समय अमेरिकी हस्तक्षेप स्वतःस्फूर्त नहीं रहेगा। यूरोप भी यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट के कारण इस क्षेत्र में प्रभावी सुरक्षा भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय शक्तियां वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की तलाश में हैं। इस बदलते परिदृश्य में एक धारा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच उभरती निकटता के रूप में दिखाई देती है, जिसे 'इस्लामिक नाटो' भी कहा जा रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग रखता आया है, किंतु हालिया वर्षों में इस संबंध को व्यापक रणनीतिक ढांचे में बदलने का प्रयास तेज हुआ है। उसकी कोशिश है कि सऊदी संसाधनों और तुर्किये की रक्षा तकनीक के साथ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा समूह बनाया जाए, जो अमेरिका पर निर्भरता कम कर सके। हालांकि इस प्रस्तावित धुरी की मजबूती उतनी नहीं है, जितनी उसकी राजनीतिक बयानबाजी से प्रतीत होती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और उसकी क्षेत्रीय विश्वसनीयता सीमित होती जा रही है। भारत के साथ उसका संघर्ष केवल भू-क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैचारिक भी है, जिसे उसकी सैन्य स्थापना अब भी 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' के रूप में जीवित रखे हुए है। इसी वैचारिक ढांचे के माध्यम से पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में समर्थन जुटाने की कोशिश करता रहा है, किंतु व्यावहारिक स्तर पर उसे बार-बार यह एहसास हुआ है कि मजहबी एकजुटता अपने आप में स्थायी रणनीतिक समर्थन की गारंटी नहीं देती। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को विविधीकृत कर रहा है। उसके अमेरिका, चीन, भारत और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ समानांतर संबंध हैं। भारत में उसके बड़े आर्थिक हित हैं। तुर्किये भी नाटो का सदस्य रहते हुए स्वतंत्र क्षेत्रीय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस प्रस्तावित धुरी में अंतर्विरोध पैदा होते हैं। सऊदी और तुर्किये दोनों ही मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व की आकांक्षा रखते हैं, जो उन्हें सहयोगी से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है। शायद इसीलिए उसने सऊदी और पाकिस्तान के सैन्य गठजोड़ में शामिल होने से इन्कार कर दिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के समानांतर एक दूसरी रणनीतिक

जानलेवा होने लगी है मोबाइल की लत

मोबाइल का प्रयोग जहां पर लोगो को बातचीत करने का प्रमुख माध्यम बना जो लोगो के लिए काफ़ी सहूलियत भरा रहा लेकिन अब मोबाइल लोगो के लिए कहीं न कहीं घातक भी सिद्ध हो रहा है। इससे लोगो को बचने की जरूरत है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां तीन नाबालिग सगी बहनों ने नौवीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, तीनों को ऑनलाइन गेम की लत थी और गेम खेलने को लेकर परिवार के मना करने पर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। तीनों बहनों की उम्र 16, 14 और 12 साल थी। पुलिस के मुताबिक तीनों बहनें कोरियन लव गेम खेलती थीं और तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम खेला करती थीं। इस घटना से कहीं न कहीं यह समझा जा सकता है कि आज देश में बच्चों और युवाओं की सोच को दिखा रहा है और इस आदत में यदि सुधार नहीं किया गया तो सच में भविष्य में और भी बड़े खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत में

2024 के मुताबिक स्क्रीन वॉच टाइम का आंकड़ा चौकाने वाला है और अब दो वर्षों में तो इसमें और इजाफा हो गया होगा। 2024 के मुताबिक भारत में हर व्यक्ति 5 घण्टे औसत मोबाइल पर बीतता है, वर्ष 2024 में भारत के लोगो ने कुल 1.1 लाख करोड़ घंटे लोगो ने मोबाइल चलाने में बिताया। भारत में लगभग 7 घंटे लोग ऑनलाइन रहते है, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत लोग सोशल मीडिया, गेम और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर समय बिताते है, देश में यदि 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों की बात की जाये तो औसत 2.2 घंटे एक बच्चा मोबाइल देखने में बीतता है क्योंकि देखा जाता है बच्चों को चुप रखने के लिए महिलाएं बच्चों को मोबाइल दे देती है।

संतोष कुमार तिवारी

> संगठन भारतीय है और इसका नेतृत्व एक सेवानिवृत्त भारतीय अधिकारी कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, 'भारत को ट्रंप की सोशल मीडिया घोषणाओं का जश्न नहीं मनाना चाहिए। 'कारा (रा) ग्रे वस्ते लक्ष्मी' सच है। लेकिन इसका मतलब है कि इस संभावित लक्ष्मी का मूल्यांकन 'कर' में 'सरस्वती' के आधार पर किया जाना चाहिए।

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में घोषित व्यापार समझौता (फरवरी 2026) पारदर्शिता की कमी, रूसी तेल आयात पर मौन और वाशिंगटन द्वारा बड़े दावों के कारण रहस्यमय और संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। हालाँकि अमेरिकी टैरिफ में 18% तक की कटौती हुई है, लेकिन पूर्ण दस्तावेज़ न होने से भारतीय कृषि और रणनीतिक स्वायत्तता पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं जैसे पारदर्शिता का अभाव - भारत सरकार ने समझौते के विशिष्ट विवरण, लिखित शर्तों या आधिकारिक पाठ को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया है, जिससे यह संदेह गहरा गया है।रूसी तेल और भू-राजनीतिक दबाव - राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल आयात बंद करने का वादा किया है, लेकिन भारत की ओर से इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, जो एक बड़ा रहस्य बना हुआ है।कृषि और डेयरी क्षेत्र पर खतराः विपक्षी दलों ने चिंता जताई है कि भारत ने अपने कृषि और डेयरी बाजारों को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दिया है, जो भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ हो सकता है।दावों में अंतर- अमेरिका ने दावा किया कि भारत $500 बिलियन से अधिक के अमेरिकी सामान खरीदेगा, जबकि भारत ने केवल टैरिफ में कमी (18% तक) पर ही ध्यान केंद्रित किया, न कि बड़ी खरीदारी के दावों पर।सं संप्रभुता का सवालः इस बात पर बहस है कि क्या यह समझौता भारत की स्वतंत्र विदेश और व्यापार नीति के अनुरूप है, या यह अमेरिकी दबाव में लिया गया कोई निर्णय है। इस प्रकार, इस समझौते को एक 'ऐतिहासिक सफलता' के बजाय 'राजनीतिक संकेत' या 'विश्वास बहाली का उपाय' अधिक माना जा रहा है तथा भारत और अमेरिका के बीच तथाकथित व्यापार समझौता बेहद रहस्यमय मामला नजर आ रहा है। देखा जाय तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस समझौते की एकतरफा घोषणा का स्वागत किया क्योंकि किसी भी कारण से किसी भी तरह के व्यापार और उद्योग का विरोध करना अवैध है, लेकिन अगर समझौते की घोषणा के 24 घंटे बाद भी किसी भी विवरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो संदेह होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच तथाकथित समझौता, जिसमें कोई विवरण, कोई क्लॉज, कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक रहस्य है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के लिए कम से कम दो पक्षों और सभी संबंधित लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि भारत को साथ नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने पारस्परिक रूप से घोषणा की कि भारत को साथ लेकर बिना किसी समझौते के दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है और अब समय आ गया है कि हम इसे एमयू कहें। उन्होंने कनाडा के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की। हालांकि, देश के प्रधान मंत्री, मार्क कार्नी ने ट्रम्प को मना लिया, और कनाडा-अमेरिका सौदा गुब्बारा गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रम्प की घोषणा पर टिप्पणी की और आश्वासन दिया कि तथाकथित समझौते से भारतीय कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हितों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। हालांकि, उसके बाद, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार के आकार की वर्तमान वास्तविकता के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में इस पर टिप्पणी के लिए लगातार दूसरे दिन टिप्पणी की आवश्यकता थी। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कथित सौदे के विवरण पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये ट्रम्प की घोषणा की रिपीट है, जिसका मतलब है कि ट्रम्प ने जो घोषणा की है, उसे अमेरिकी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और उसी के अनुसार आगे भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। पहला मुद्दा भारत की तेल खरीद का है, हम रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है। ट्रम्प और लेविट यही कहते हैं। लेकिन तेल खरीदना पानी का नल नहीं है। जब आप इसे चालू करेंगे, तो पानी आएगा और जब आप इसे बंद करेंगे, तो यह बंद हो जाएगा। ये खरीद समझौते, जो हफ्तों और महीनों पहले किए जाते हैं, क्या उन्हें अचानक रद्द किया जा सकता है क्योंकि ट्रम्प ऐसा कहते हैं? उत्तर सकारात्मक हो सकता है, लेकिन इस तरह के समझौतों में अक्सर मुआवजे का मुद्दा शामिल होता है, जो खरीद को एकतरफा रद्द करने और दूसरे पक्ष को नुकसान को रोकने के लिए है। यदि भारत और रूस के बीच तेल सौदा समाप्त हो जाता है तो भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के बारे में क्या? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वेनेजुएला के तेल और रूसी तेल के बीच एक मूलभूत अंतर हैः रूसी तेल हल्का और परिष्कृत करने में आसान है, और वेनेजुएला का तेल इसके ठीक विपरीत है, और यह सल्फर और अन्य प्रदूषकों के साथ भी अधिक प्रदूषणकारी है। और क्या उन्हें इसे सबसे पहले करना चाहिए? क्योंकि आप रूसी तेल को मौजूदा बाजार मूल्य की तुलना में 10 डॉलर प्रति बैरल सस्ता करते हैं, क्या आप इस लाभ को छोड़ देंगे क्योंकि ट्रम्प ऐसा सोचते हैं? ट्रम्प और लेविट के बीच दूसरा मुद्दा इस घोषणा के बारे में है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका से $ 50,000 बिलियन मूल्य का सामान खरीदेंगे, जो न केवल एक बड़ी राशि है, बल्कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वर्तमान कारोबार केवल $ 4100 बिलियन है, और यदि आप सेवा क्षेत्र में लेनदेन मूल्य जोड़ते हैं, तो यह समान राशि से बढ़कर $ 8,000 बिलियन हो जाएगा, यानी हम संयुक्त राज्य अमेरिका से जो सामान और सेवाएं खरीदते हैं यह 50 ट्रिलियन डॉलर तक कैसे बढ़ सकता है? एक व्यवसाय ऐसे समय में 500 प्रतिशत कैसे बढ़ सकता है जब यह निश्चित है कि एक बकवास को छोड़कर कुछ भी इतनी तेजी से बढ़ सकता है? इस पर कुछ सरकारी समझदार लोगों का कहना है कि 50 हजार करोड़ डॉलर का लक्ष्य पांच साल का है; पहले वर्ष में नहीं। यह एक बार है, लेकिन यदि आप ऐसा करते भी हैं, तो आपको पहले वर्ष में $4100 मिलियन से संयुक्त राज्य अमेरिका से $10,000 बिलियन मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं खरीदनी होंगी, एक ही वर्ष में 100 प्रतिशत की वृद्धि? ट्रंप और लेविट का तीसरा मुद्दा यह है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर शून्य प्रतिशत और अमेरिका में बिकने वाले भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत शुल्क लगाएगा। लेकिन जिन्हें साधारण एक्सचेंजों का व्यावहारिक ज्ञान है, वे भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। हम 18 प्रतिशत टैरिफ कैसे दे सकते हैं और अमेरिकी उत्पादों पर सभी करों को छूट कैसे दे सकते हैं। वर्तमान में, हम उस देश के उत्पादों पर 16 प्रतिशत का न्यूनतम आयात शुल्क लगाते हैं जिसे हमने 'विशेष दर्जा' दिया है, जिसका अर्थ है कि जब उस देश के उत्पाद भारतीय बाजार में पहुंचते हैं, तो उनकी कीमत 16 प्रतिशत बढ़ जाती है, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क 36.8 प्रतिशत है और कुछ उत्पादों के लिए 64.3 प्रतिशत है। यह है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, तो विदेशी उत्पाद भारतीय बाजार में घरेलू उत्पादों की तुलना में सस्ते होंगे, और हमारे किसान, उद्यमी सचमुच बर्बाद हो जाएंगे। और ट्रम्प कहते हैं कि भारत इन उत्पादों पर आयात शुल्क को पूरी तरह से हटाने के लिए सहमत हो गया है, ऐसा करना असंभव है। इसके ऊपर से जैसा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है, अगर अमेरिकी उत्पादों से कृषि और डेयरी के हितों को नुकसान नहीं पहुंचता है तो ट्रंप की घोषणा एक अचार होगी।

■ अशोक भाटिया

जन सुराज का... — अमरपाल सिंह वर्मा

सेब से खेजड़ी तकः विकास बनाम पर्यावरण की एक जैसी लड़ाई

केंद्र सरकार ने हाल ही में कश्मीर में प्रस्तावित तीन रेलवे परियोजनाओं पर रोक लगाकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। यह फैसला सेब के बागों को बचाने के लिए लिया गया है, जिन पर इन रेल लाइनों के निर्माण से सीधा खतरा मंडरा रहा था। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय है बल्कि उन किसानों के लिए भी बड़ी राहत है जिनकी आजीविका सेब के बागों पर निर्भर है। प्रस्तावित रेलवे लाइनों के कारण पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग जैसे इलाकों में सेब के हजारों पेड़ों के कटने की आशंका थी। ये इलाके कश्मीर के सेब उत्पादन का केंद्र हैं और वहां की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। बीते एक साल से किसान इस डर में जी रहे थे कि विकास के नाम पर उनकी जमीन और रोजगार छिन जाएगा। इसी आशंका के चलते किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किए और सरकार से इन परियो-जनाओं को रद्द करने की मांग की। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर सरकार और राज्य के सांसदों की सिफारिश पर इन परियोजनाओं को रोका गया है ताकि बागों को नुकसान से बचाया जा सके। यह निर्णय इस बात की मिसाल है कि यदि सरकार चाहे, तो वह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना सकती है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या यही संवेद-नशीलता देश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई जा रही है? इस सवाल के जवाब में राजस्थान के बीकानेर में चल रहा 'खेजड़ी बचाओ-प्रकृति बचाओ' आंदोलन ध्यान खींचता है। यह आंदोलन राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के नाम पर हो रही

पर्यावरणीय क्षति के विरोध में खड़ा हुआ है। इस आंदोलन के तहत पर्यावरण संघर्ष समिति ने बीकानेर में तीन दिन पहले महापड़ाव डाला है। महापड़ाव स्थल पर आमरण अनशन पर पहले 363 पर्यावरण प्रेमी बैठे, जिनकी संख्या बाद में 450 हो गई। इनमें 29 संत, एक साध्वी और 68 महिलाएं हैं। अनशन पर 18 के युवा से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। कल तीसरे दिन आमरण अनशन पर बैठे 17 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई। 3 को गंभीर हालत में पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा है। अब अनशनस्थल पर 75 बेड के 2 अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। यह आदोलन राजस्थान मे खेजड़ी बचाने के लिए किया जा रहा है। अनशन-कारियों की बिगड़ती तबीयत और अस्थाई अस्पतालों की व्यवस्था इस आंदोलन की गंभीरता को दर्शाती है। यह सर्वविदित है कि राजस्थान आज देश में सौर ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। सरकार और कंपनियों का दावा है कि इससे भविष्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और देश का ऊर्जा परिदृश्य बदलेगा लेकिन इस विकास की कीमत क्या है, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राजस्थान में पिछले एक दशक में लाखों पेड़ काटे गए हैं। इनमें खेजड़ी जैसे पारंपरिक और जीवनदायी वृक्ष भी शामिल हैं। खेजड़ी को राजस्थान में 'कल्प वृक्ष' का दर्जा प्राप्त है। यह न केवल मरुस्थलीय पर्यावरण को संतुलन देता है बल्कि इससे सांगरी जैसी सब्जी, पशुओं के लिए चारा और ग्रामीण समुदाय की आजीविका भी जुड़ी हुई है। जन्म से मृत्यु तक के सामाजिक संस्कारों में भी खेजड़ी की मौजूदगी अपरिहार्य है। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के प्रो. अनिल छंगाणी की स्टडी में यह तथ्य उजागर हुआ है कि सोलर लगाने के लिए 10 साल में 50 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। इनमें खेजड़ी, बेर, केर, रोहिड़ा, बबूल आदि शामिल हैं। अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि सौर प्लांटों के आसपास का तापमान औसतन 4-5 डिग्री तक बढ़ जाता है। पेड़ों की कटाई से कीट-पतंगों, मधुमक्खियों, पक्षियों और अन्य जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। गोंद और चारे की उपलब्धता घट रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। इसके अलावा, सौर संयंत्रों को साफ और ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है जबकि राजस्थान पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है। यह सच है कि सौर ऊर्जा समय की जरूरत है। कोयला, परमाणु और गैस आधारित बिजली उत्पादन से प्रदूषण फैलता है और कोयले के भंडार भी सीमित हैं। ऐसे में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना अपरिहार्य है। लेकिन क्या इसका मतलब यह होना चाहिए कि पर्यावरण और पारंपरिक जीवन प्रणालियों की अनदेखी कर दी जाए? यहीं पर कश्मीर और बीकानेर के मामलों की तुलना करना आवश्यकता लगता है। कश्मीर में सरकार ने सेब के बागों को बचाने के लिए विकास परियोजनाओं पर रोक लगाई। वहां यह माना गया कि किसानों की आजीविका और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कर विकास का कोई औचित्य नहीं है। वहीं राजस्थान में खेजड़ी और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण की मांग करने वालों को अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कश्मीर के सेब के बाग और राजस्थान की खेजड़ी दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था और संस्कृति के आधार हैं। अंतर केवल इतना है कि एक मामले में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है जबकि दूसरे मामले में अब भी आवाजें अनसुनी हैं। सवाल है कि क्या विकास की परिभाषा क्षेत्र के अनुसार बदल जानी चाहिए? क्या एक राज्य के पेड़ ज्यादा कीमती हैं और दूसरे के कम? जरूरत इस बात की है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्पष्ट और सख्त पर्यावरणीय नियम बनाए जाएं। कंपनियों को पेड़ कटाई, जल उपयोग और स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए जवाबदेह ठहराने की जरूरत है।

अमेरिका से समझौता ... — राजेश कुमार पासी

ट्रेड डील-जीत को हार बताने की कोशिश

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो गया है हालांकि अभी उस पर हस्ताक्षर नहीं किये गए हैं। जो लोग आरोप लगा रहे थे कि मोदी के कारण दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है और हमारे देश पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है, वही लोग अब कह रहे हैं कि मोदी झुक गए हैं और देशहित से समझौता कर लिया है। देश के किसान और छोटे व्यापारी इस समझौते से बर्बाद हो जाएंगे। इस समझौते की अहमियत कम करने के लिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है जबकि सच्चाई यह है कि भारत पर टैरिफ 50% से घटकर 18% हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया में कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदने से मना कर दिया है जबकि भारत सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। अजीब बात है कि जो विपक्ष पिछले 6 महीनों से लगातार कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से डरकर मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, वही विपक्ष अब कह रहा है कि अमेरिका के दबाव में अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। सवाल यह है कि अगर 6 महीने पहले ही भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया था तो अब कैसे दोबारा यही काम होगा । भारत में विपक्ष और उसका समर्थक वर्ग झूठ बोलने का इतना आदी हो गया है कि उसे पता नहीं चलता कि उसने कल क्या बोला था। अगर अमेरिका से व्यापार समझौता नहीं हो रहा था तो उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है और अब हो गया है तो मोदी सरकार को श्रेय देने की जगह कठघरे में खड़ा किया जा रहा

है । राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी ने भारत को बेच दिया है जबकि सच्चाई यह है कि ये बात वो पिछले 11 साल से लगातार बोल रहे हैं। अगर इस समझौते से भारत को बेचा गया है तो अभी तक भारत नहीं बिका था। एक चीज़ बार-बार तो नहीं बिक सकती। अगर भारत आज बिका है तो पहले नहीं बिका था। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि वो 11 साल से किसके बिकने का शोर मचा रहे थे। क्या व्यापार समझौता करके कोई देश बिक सकता है, अजीब बात कही जा रही है। अमेरिका से समझौता नहीं होने से अगर भारत का नुकसान हो रहा था तो समझौता होने से क्यों नुकसान होगा। विपक्ष को पता ही नहीं है कि वो चाहता क्या है। उसे हर हाल में सरकार का विरोध करना है और हर काम के लिए उसकी आलोचना करनी है। जीत को भी हार बताना है, ताकि सरकार को किसी भी तरह का श्रेय न मिले। विपक्ष का कहना था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो भारत में बेरोजगारी पैदा होगी, देश को आर्थिक नुकसान होगा । जब समझौता हो गया है तो फिर कहा जा रहा है कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा। विपक्ष तय नहीं कर पा रहा है कि समझौता होने से देश बर्बाद होगा या नहीं होने से होगा।

जरा हटके

कहना न होगा ... — कमलेश पाण्डेय

आखिर घाटे वाले विदेश व्यापार को मुनाफे वाले कारोबार में कब और कैसे बदलेगा भारत?

भारत की सियासत 'वैचारिक अकाल' से पीड़ित है, जिसका असर हमारे घरेलू कारोबार के अलावा विदेश व्यापार पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। सच कहूं तो राष्ट्र की 'आर्थिक स्वायत्तता' ही चीन और रूस जैसे देशों के समक्ष गिरवी प्रतीत हो रही है। यह ठीक है कि रूस हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मददगार मित्र है, जिसके द्वारा शोषण किया जाना स्वाभाविक है। लेकिन चीन जैसे मजबूत और पड़ोसी शत्रु देश को इतना भारी कारोबारी लाभ देने के बावजूद यदि हम उसे अपना मित्र नहीं बना पाए तो यह बात सिर्फ यही चुगली करती है कि हमारी आंतरिक दलित और पिछड़ी नीतियों की वजह से भारत रणनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछड़ता प्रतीत होता हैं। यही वजह है कि आर्थिक विशेषज्ञ यह सवाल दाग रहे हैं कि आखिर घाटे वाले विदेश व्यापार को मुनाफे वाले अंतरराष्ट्रीय कारोबार में कब और कैसे बदलेगा भारत? देखा जाए तो भारत का विदेश व्यापार वर्तमान में भारी घाटे में है, जो दिसंबर 2025 में 25 अरब डॉलर तक पहुंच गया। विपरीत स्थिति यानी कारोबारी घाटा चीन, रूस, यूएई और इराक जैसे 75 देशों के साथ है जहां व्यापार घाटा हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहां से आयात निर्यात से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए, हमारा सरकारी प्रयास निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित हैं, लेकिन अधिशेष (सर्विस ट्रेड को छोड़कर गुड्स ट्रेड में) प्राप्त करने का कोई निश्चित समयसीमा नहीं है। वर्तमान स्थिति में भारत का व्यापार घाटा एफवाई (FY) 2026 के पहले क्वार्टर में एफटीए (FTA) देशों के साथ 59% बढ़कर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया, जहां निर्यात 9% गिरा और आयात 10% बढ़ा। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2025 में यह 25.04 अरब डॉलर रहा, जबकि अनुमान 2027 तक -32 अरब डॉलर का है। यानी वर्तमान के साथ साथ निकट भविष्य भी अंधकारमय है। खासकर रूस, चीन और आसियान जैसे साझेदारों के साथ ही घाटा प्रमुख समस्या बनी हुई है। रूस तो भारत का भरोसेमंद मित्र

है, हथियार व तकनीकी आपूर्तिकर्ता है। लेकिन चीन के खिलाफ आसियान देश समूह को संतुलित करने/रखने की नीति हम पर अब भारी महसूस हो रही है। लुक ईस्ट की नीति भी सफेद हाथी साबित हुई। हां, लाभ देने वाले पश्चिमी देशों को यदि विकल्प दिखाकर काबू में रखना है तो फिर कुछ नहीं कहना। क्योंकि यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होते ही अमेरिकी अकड़ ढीली पड़ गई और उसके साथ भी एफटीए हो गया। हालांकि भारत की कारोबारी चुनौतियाँ यह हैं कि चीन, रूस और कोरिया के अलावा स्विट्जरलैंड, यूएई, इराक जैसे देशों से आयात अधिक है, जबकि अमेरिकी कूटनीतिक व रणनीतिक टैरिफ ने निर्यात प्रभावित किया, जबकि अब इसका खतरा टल गया है क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, एफटीए (FTA) के बावजूद आसियान निर्यात गिरा, और सोना-तेल आयात घाटा बढ़ा रहा। मसलन, लॉजिस्टिक्स, अनुपालन लागत और वैश्विक टैरिफ हमारे विदेश व्यापार की प्रमुख बाधाएँ हैं। फिर भी भविष्य की संभावनाएँ बरकरार हैं। खासकर घाटा कम करने के लिए निर्यात विविधीकरण, जीवीसी (GVC) एकीकरण और अवसंरचना सुधार आवश्यक हैं, लेकिन पूर्वानुमान 2027 तक भी घाटा दिखाते हैं। कहना न होगा कि भारत का विदेश व्यापार घाटा मुख्य रूप से चीन, रूस, स्विट्जरलैंड, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ है। दरअसल, यह घाटा ऊर्जा आयात, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे माल की उच्च निर्भरता के कारण बढ़ रहा है। इसलिए भारत को नीतिगत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन घाटों पर काबू पाना होगा। आंकड़े बताते हैं कि भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से अधिकांश (शीर्ष 10 में 9) के साथ हमारा घाटा वाला कारोबार हैः- पहला, चीनः सबसे बड़ा घाटा (2024-25 में $99.2 बिलियन, 2025 में $116 बिलियन तक), वजह- इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, APIs और केमिकल्स आयात से। बताया जाता है कि उपर्युक्त देशों से घाटे के कारण रणनीतिक तैयारियों में कमियां और भीतरघात की सियासत व कूटनीति है। इन देशों से व्यापार घाटा का मतलब है कि भारत में इन देशों से आयात ज्यादा है, जबकि इन देशों को भारत से निर्यात कम होने से है, खासकर ऊर्जा (तेल 80% आयातित) और मैन्युफैक्च-रिंग इनपुट्स क्षेत्र में।जहां चीन के साथ संकीर्ण निर्यात (कच्चा माल), बाजार बाधाएं, और सस्ते आयात की समस्या है। वहीं, रूस/यूएई से तेल आयात में वृद्धि, और निर्यात सम्बन्धी बाधाएं हैं। इस तरह से मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वाले देशों के साथ घाटा 59% बढ़ा (2025-Q1) है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2025 में कुल घाटा $25 बिलियन तक पहुंच चुका है। वित्त वर्ष (FY) 25 में चीन के साथ यह रिकॉर्ड उच्च स्तर है। जबकि सरकार पीएलआई (PLI) जैसी आकर्षक योजना से आयात कम करने की कोशिश कर रही है। सवाल है कि मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वाले देश कौन कौन से हैं जिनके साथ भारत का घाटा बढ़ा है, तो जवाब होगा कि भारत के एफटीए (FTA) देशों के साथ व्यापार घाटा अप्रैल-जून 2025 (Q1 FY26) में 59.2% बढ़कर $26.6 बिलियन हो गया है। कहने का तातपर्य यह कि भारत में आयात 10% बढ़े जबकि निर्यात 9% गिरे, जो हमारी रणनीतिक आर्थिक चौकसी में कमी को दर्शाता है नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित देश भारत के विदेश व्यापार घाटे में योगदान दे रहे हैं। इन देश/समूह से कारोबारी घाटे का कारण/ट्रेंड निम्नलिखित हैं- इसका कारण आसियान (ASEAN) के साथ पुनर्समझौता में देरी और आयात में इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल की वृद्धि हुई; जबकि निर्यात में कमी आई है। वहीं, FTA पुनः समझौता (renegotiation) भी लंबित है। शायद इसलिए सरकारी रणनीतियाँ बदली हैं। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) के तहत 25,060 करोड़ रुपये की योजना 2025-31 तक चल रही, जिसमें ब्याज सब्वेंशन, क्रेडिट गारंटी और ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 (बिना समाप्ति तिथि) निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, SEZ को मजबूत करती है और RoDTEP जैसे स्कीम्स बहाल किए गए। जबकि चीन से घाटा कम करने हेतु पीएम नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत पर जोर दिया है।

भारतीय पिचों पर कैरेबियाई और इंग्लिश खिलाड़ियों की कड़ी परीक्षा

ग्रुप सी से बाहर हुआ बांग्लादेश, इंग्लैंड-वेस्टइंडीज की राह आसान

नई दिल्ली, एजेंसी

टी20 विश्व कप की शुरुआत में ग्रुप सी को 'ग्रुप ऑफ डेथ' माना जा रहा था, लेकिन बांग्लादेश के भारत में नहीं खेलने की मांग के चलते आईसीसी ने उसे बाहर कर स्कॉटलैंड को इस ग्रुप में शामिल कर दिया। भारतीय उपम-हाद्वीप की परिस्थितियों में बांग्लादेश बाकी टीमों के लिए कठिन प्रतिद्वंद्वी साबित होता और इसलिए ये ग्रुप सबसे रोमांचक माना जा रहा था, लेकिन अब समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। ग्रुप में दो-दो बार ट्रॉफी जीतने वाली वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के अलावा पहली बार विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली इटली, नेपाल और स्काटलैंड है।

चौंकाने उतरेंगे इटली-स्कॉटलैंड, उलटफेर में सक्षम हैं

दोनों टीम ग्रुप की बाकी दो टीमों की बात करें तो इटली की टीम ने पहली बार टी-20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है और उसकी इस सफलता में आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जो बर्न्स का बड़ा हाथ रहा है। वहीं स्कॉटलैंड ने भाग्य के सहारे जगह बनाई है। बांग्लादेश के हटने पर उसे मौका मिला है।

वेस्टइंडीज में अब अधिकतर खिलाड़ी टी-20 क्रिकेट को ही प्राथमिकता देते हैं और दुनियाभर की टी-20 लीग में खेलते हैं। टीम में कई खिलाड़ी हैं, जो आइपीएल में खेलते हैं और भारत की परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित हैं। हाल ही में उसके ज्यादातर खिलाड़ी हाल ही में एसए20 खेलकर आए हैं और शेरफान रदरफोर्ड तो जबरदस्त फार्म में चल रहे हैं। इस ग्रुप से इंग्लैंड के बाद अब वेस्टइंडीज का नाकआउट चरण में पहुंचने की संभावना सबसे अधिक हैं।

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की राह आसान

बांग्लादेश के हटने से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की अगले दौर में पहुंचने की राह थोड़ी आसान हुई है। 2010 और 2022 में खिताब जीत चुकी इंग्लैंड की टीम की कमान इस बार हैरी ब्रूक के हाथों में हैं, जो हाल ही में मैदान से ज्यादा मैदान के बाहर अपने व्यवहार के लिए चर्चा में रहे थे। ब्रूक पिछले साल जोस बटलर की जगह सीमित ओवर प्रारूप में कप्तान बनने के बाद पहली बार किसी वैश्विक टूर्नामेंट में कमान संभाल रहे हैं। हालांकि अगर इंग्लैंड का 2022 टी-20 विश्व कप के बाद के प्रदर्शन को देखें तो 2023 वनडे विश्व कप में टीम ग्रुप चरण से ही बाहर हो गई थी।

लगातार दूसरी बार नेपाल ठोकेगा ताल

तीन करोड़ से अधिक आबादी वाला देश तब अपने 15 क्रिकेटरों पर उम्मीदें लगाएगा जब नेपाल लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने के बाद आठ फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले मैच के लिए वानखेड़े स्टेडियम में उतरेगा। नेपाल की टीम ऐसी है जिसे कभी बुनियादी ढांचे के लिए संघर्ष करना पड़ा था और इसलिए विश्व कप में उसकी भागीदारी को बड़ी छलांग के रूप में देखा जा रहा है। जब रोहित पौडेल की अगुवाई वाली नेपाल की टीम मैदान पर उतरेगी तो उसे बड़ी संख्या में अपने प्रशंसकों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। नेपाल के पास इटली और स्काटलैंड दोनों को हराने का अच्छा मौका है। अगर वे इंग्लैंड या वेस्टइंडीज में से किसी एक को हराने में कामयाब हो जाते हैं, तो वे अगले दौर में पहुंच जाएंगे।

हरियाणा के खिलाड़ियों का जर्मनी में दबदबा

नारनौल। जर्मनी के शहर पोट्सडम में आयोजित 5वीं ओपन इंटरनेशनल मास्टर्स वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए। इन पदकों में 3 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में हरियाणा के दो खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। हरियाणा मास्टर वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी व नारनौल की कविता ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की ओर से 10 सदस्यों की टीम ने भाग लिया। टीम का नेतृत्व भारतीय मास्टर्स वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी उदय शेट्टी की अगुवाई में किया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा के भिवानी जिला के संदीप कुमार ने 65 किलो पुरुष भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की, जबकि हरियाणा के ही ज्योति प्रकाश ने 110 किलो पुरुष भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। पंजाब के संतोष कुमार ने 110 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

ईशान को बैटर्स रैंकिंग में 32 स्थान का फायदा

ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान के सईम अयूब नंबर-1

दुबई, एजेंसी

भारतीय बैटर ईशान किशन को ICC रैंकिंग में 32 स्थान का फायदा हुआ है। बुधवार को जारी प्लेयर्स रैंकिंग में ईशान 584 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 32वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के सईम अयूब ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने जिम्बाब्वे के अनुभवी खिलाड़ी सिकंदर रजा को पीछे छोड़ा। भारत के शिवम दुबे को भी ऑलराउंडर्स में दो स्थान का फायदा हुआ। वे अब 186 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 11वें से नौवें पायदान पर पहुंच गए हैं। टी-20 बल्लेबाजों की टॉप-10 रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के जोस बटलर, श्रीलंका के पथुम निसांका, भारत के सूर्यकुमार यादव और न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। वहीं चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेलने वाले तिलक वर्मा को एक

स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। विकेट-कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। वे पांच मैचों की सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। ईशान ने चार मैचों में कुल 215 रन बनाए। पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद टी-20 गेंदबाजों की रैंकिंग में दो स्थान की बढ़त के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वह अब भारत के वरुण चक्रवर्ती से सिर्फ 28 रेटिंग पॉइंट्स पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों में उन्होंने छह विकेट चटकाए।

फास्ट न्यूज

5 साल बाद रिया चक्रवर्ती की एक्टिंग में वापसी

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लंबे समय तक ब्रेक लेने के बाद रिया चक्रवर्ती फिर से फिल्मों और सीरीज में वापसी कर रही हैं। मंगलवार शाम वह मुंबई में हुए 'Next On Netflix' इवेंट में शामिल हुईं, जहां एक्ट्रेस ने अपनी कमबैक सीरीज फैमिली बिजनेस की आधिकारिक घोषणा की। इस सीरीज में रिया के साथ अनिल कपूर और विजय वर्मा भी नजर आएंगे।

अमेरिकी अखबार में छंटनी-शशि थरूर के बेटे की नौकरी गई

वॉशिंगटन। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को 800 पत्रकारों में से 300 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। इसमें सीनियर कॉलमिस्ट ईशान थरूर भी शामिल हैं। वे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे हैं। ईशान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वॉशिंगटन पोस्ट ने इंटरनेशनल टीम के कई शानदार पत्रकारों के साथ उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया है। यह न्यूज रूम के लिए बेहद दुखद दिन है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मैट मरे ने बताया कि जेफ बेजोस की कंपनी पिछले कई सालों से घाटे में चल रही थी। इस छंटनी में स्पोर्ट्स सेक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, हालांकि कुछ रिपोर्टर फीचर्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट होकर स्पोर्ट्स की कल्चर कवरेज जारी रखेंगे।

समंदर में 4 घंटे तैरता रहा 13 साल का बच्चा

पर्थ। ऑस्ट्रेलिया में 13 साल के एक बच्चे ऑस्टिन एपलबी ने समुद्र में करीब 4 घंटे तैरकर अपनी मां और दो छोटे भाई-बहनों की जान बचाई। वह परिवार के साथ समुद्र में गया था। अचानक लहरें तेज हो गईं। बोट पलटने से सभी बहते हुए समुद्र में 14 किमी दूर निकल गए थे। द गॉर्जियन के मुताबिक, जोआन एपलबे अपने बच्चों ऑस्टिन, ब्यू और ग्रेस के साथ पर्थ से करीब 200 किलोमीटर दूर क्विंडलप में छुट्टियां मना रही थीं।

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर विवाद

मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा गया, 'पंडित' शब्द को अपमानित करने का आरोप

मुबंई। मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी नई फिल्म घूसखोर पंडत को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक इवेंट में फिल्म का टीजर जारी किया गया, जिसके बाद यह विवादों में घिर गया। मुंबई के एक वकील का आरोप है कि 'पंडित' जैसे सम्मानजनक शब्द को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण उन्होंने फिल्म के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नोटिस मुंबई के वकील आशुतोष दुबे ने भेजा है। उनका आरोप है कि 'पंडित' जैसे सम्मानजनक शब्द को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ना न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि इससे पूरे समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचती है। नोटिस में कहा गया है कि यह फिल्म जानबूझकर एक समुदाय की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। 'पंडित' शब्द भारतीय सभ्यता में नैतिकता और आध्यात्मिक अधिकार का प्रतीक है। इसे रिश्वतखोरी और अपराध के साथ जोड़कर दिखाना गलता है।

पैसे नहीं थे तो अवॉर्ड शो में पहनी पुरानी शेरवानी, विल स्मिथ का तोड़ा रिकॉर्ड

50 साल के हुए अभिषेक

मुबंई। एक्टर अभिषेक बच्चन आज अपना 50वां बर्थडे मना रहे हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के घर जन्मे अभिषेक की पहचान सिर्फ एक सुपरस्टार के बेटे तक सीमित नहीं रही। उम्मीदों, असफल-ताओं, आलोचनाओं और फिर सफलता के चक्र से गुजरते हुए उन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई और युवा, धूम, गुरु जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। अभिषेक ने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश और जमनाबाई नरसी स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली के वसंत विहार स्थित मॉडर्न स्कूल और फिर स्विट्जरलैंड के ऐग्लॉन कॉलेज में शिक्षा हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए वह बोस्टन यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता की कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ABCL) के दिवालिया होने पर मुश्किल वक्त में परिवार का साथ देने के लिए उन्होंने डिग्री पूरी होने से पहले ही कॉलेज छोड़ दिया और भारत लौट आए। गलगाटा प्लस मेगा हिंदी राउंडटेबल 2023 में अभिषेक ने बताया था कि एक अवॉर्ड फंक्शन में मजबूरी में वह अपनी बहन की शादी में पहनी गई शेरवानी पहनकर पहुंचे थे, क्योंकि उस कठिन दौर में उनके पास नए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अभिषेक ने मैशेबल इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि इस दौरान उन्होंने चाय बनाई, शूटिंग शुरू होने से पहले सेट की सफाई की, फर्श साफ किया, लाइट्स उठाईं और ट्रॉली तक धकेली।

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी व अभिषेक बच्चन की बड़ी बहन का नाम श्वेता बच्चन नंदा है।

एक्टर ने बताया था कि जब वह अपनी पहली फिल्म रिफ्यूजी की शूटिंग कर रहे थे और अपना पहला ही शॉट देने वाले थे, तो उस दिन शूटिंग देखने के लिए काफी लोग जमा हो गए थे। सबको यह जानने की उत्सुकता थी कि अमिताभ बच्चन का बेटा कैमरे के सामने कैसा प्रदर्शन करता है। आसपास के गांवों से लेकर पूरी स्टारकास्ट तक, सभी लोग यह देखने आए थे कि अभिषेक अपने पहले शॉट में क्या करते हैं?

अभिषेक बच्चन को बचपन में डिस्लेक्सिया (सीखने की बीमारी) थी, जिसका जिक्र फिल्म तारे जमीन पर में भी किया गया है।

सेट साफ किया, फर्श पोछा

कॉलेज छोड़ने के बाद अभिषेक ने ABCL में काम शुरू किया। वहां वह ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठते थे, रजिस्टर संभालते थे और आने-जाने वाले हर व्यक्ति से साइन करवाते थे। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी काम किया। वहां वह एक तरह से प्रोडक्शन बॉय बन गए। मैशेबल इंडिया को दिए इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया था कि जब आपके पिता एक ओवरअचीवर रहे हैं, तो क्या उनकी तरह कुछ नया और बड़ा कर दिखाने का प्रेशर आप पर भी रहता है।

भारत किसी से भी तेल खरीदने के लिए आजाद : रूस

इसमें कुछ भी गलत नहीं, प्रवक्ता बोले- भारत से तेल खरीद रोकने की जानकारी नहीं

मॉस्को, एजेंसी

रूस ने बुधवार को कहा कि भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह आजाद है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस कभी भी भारत का एकमात्र एनर्जी पार्टनर नहीं रहा है इसलिए अगर भारत तेल की खरीद किसी और देश से करता है, तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, इस तरह की कोई भी ऑफिशियल जानकारी भारत की ओर से नहीं दी गई है। उन्होंने एक दिन पहले भी यही बात कही थी कि नई दिल्ली से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोमवार को कहा था कि भारत, अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के तहत रूस से तेल खरीद रोकने को तैयार हो गया है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है। इसके तहत भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है।

एनर्जी एक्सपर्ट बोले- रूसी तेल बंद हुआ तो कीमतें बढ़ेंगी

युशकोव ने कहा कि भारत का रूसी तेल खरीदना कोई 'एक झटके में' होने वाला काम नहीं है। ट्रम्प यह दिखाना चाहते हैं कि उनकी वजह से भारत रूसी तेल छोड़ देगा, लेकिन हकीकत इतनी सरल नहीं है। युशकोव ने याद दिलाया कि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो पश्चिमी देशों ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया या बंद कर दिया रूस ने अपने तेल को यूरोप-अमेरिका से हटाकर भारत जैसे देशों की तरफ मोड़ दिया। इस दौरान रूस ने अपना तेल उत्पादन लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन (1 मिलियन बैरल/दिन) कम कर दिया।

एक्सपर्ट बोले- रूस जितना तेल सप्लाई करना अमेरिका के लिए मुश्किल

एनर्जी एक्सपर्ट इगोर युशकोव ने यह भी कहा कि रूस भारत को रोजाना 1.5 से 2 मिलियन बैरल तक तेल भेजता है। यह बहुत बड़ी मात्रा है। अमेरिका इतनी बड़ी मात्रा में तेल आसानी से भारत को नहीं सप्लाई कर सकता। अमेरिका के पास इतनी क्षमता या तैयार सप्लाई चेन नहीं है जो इतनी जल्दी और इतने बड़े वॉल्यूम में मैच कर सके। अगर भारत अचानक रूसी तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दे और अमेरिका या किसी और से तेल लेने की कोशिश करे।

रूसी प्रवक्ता बोलीं- तेल खरीदी दोनों देशों के लिए फायदेमंद

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने रूस और भारत के बीच हाइड्रोकार्बन व्यापार जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा भारत की रूसी हाइड्रोकार्बन की खरीद दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। हम अपने भारतीय साझेदारों के साथ निकट सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं।

"इस बीच रूस के एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के लिए रूसी तेल को पूरी तरह छोड़कर किसी और देश का तेल लेना आसान नहीं है। नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी फंड के विशेषज्ञ इगोर युशकोव ने बताया कि अमेरिका जो तेल बेचता है, वह हल्का होता है, जबकि रूस, भारत को भारी और सल्फर वाला यूराल्स क्रूड सप्लाई करता है जिसका इस्तेमाल भारतीय रिफाइनरियां करती हैं।"

डोभाल की बैकडोर बातचीत के बाद अमेरिकी ट्रेड डील

वदेश मंत्री से कहा था- भारत झुकेगा नहीं

नई दिल्ली/वॉशिंगटन, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल सितंबर की शुरुआत में चीन गए थे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दोस्ताना मुलाकात की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों को संभालने की कोशिशें तेज कर दीं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल को वॉशिंगटन भेजा गया। वहां उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बातचीत में डोभाल ने साफ कहा कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है।

हालांकि, डोभाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी टीम सख्त रुख अपनाती है, तो भारत मौजूदा सरकार के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार भी कर सकता है। भारत इससे पहले भी अमेरिका की मुश्किल सरकारों का सामना कर चुका है। उस वक्त भारत ट्रम्प के बयानों से नाराज था, क्योंकि अगस्त में ट्रम्प ने भारतीय सामान पर 50% टैक्स लगा दिया था।

गिरावट : वायदा बाजार में भाव 2.40 लाख/किलो पर आया, 10 ग्राम सोना 3 हजार रुपए सस्ता

चांदी ₹28 हजार सस्ती हुई

नई दिल्ली, एजेंसी

गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार दो दिन की तेजी के बाद आज 5 फरवरी को गिरावट है। वायदा बाजार (MCX) में चांदी का दाम करीब 28 हजार रुपए (11%) कम हो गया है। 1 किलो चांदी का भाव 2.40 लाख रुपए पर आ गया है। सोने का दाम भी करीब 3 हजार रुपए (2%) गिर गया है। 10 ग्राम सोना 1.50 लाख रुपए पर है। इससे पहले 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच चांदी की कीमत 1.60 लाख रुपए कम हुई थी। वहीं सोने की कीमत में 26 हजार रुपए कम हुई थी। सर्राफा बाजार के दाम दोपहर 12 बजे जारी की जाएंगे। कमोडिटी मार्केट में जब कोई बड़ा सौदा करता है, तो उसे पूरे पैसे तुरंत नहीं देने होते। उसे कुल कीमत का एक छोटा हिस्सा सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है, जिसे 'मार्जिन' कहते हैं। मार्जिन बढ़ने का मतलब है।

सोने-चांदी में गिरावट की 2 वजह

- प्रॉफिट बुकिंगः सोने-चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया।
- फिजिकल डिमांड में कमीः ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ीं।

मार्जिन बढ़ने से सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव

सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) ने कॉपर के बाद अब सोने और चांदी पर भी मार्जिन मनी बढ़ा दी है। सोने पर मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया है। वहीं चांदी पर इसे 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।

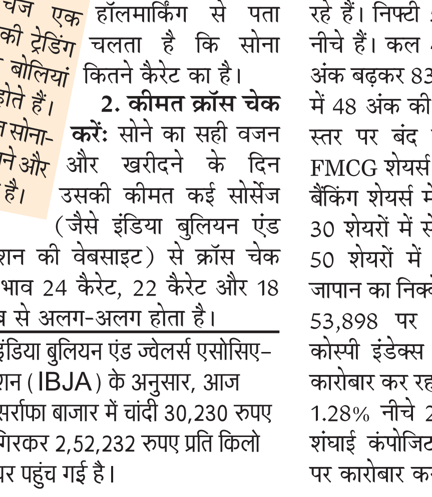

एमसीएक्स और सर्राफा बाजार में दाम अलग-अलग क्यों?

- **MCX :** मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सोने-चांदी की ट्रेडिंग होती हैं। शेयर बाजार की तरह हर सेकंड बोलियां लगती हैं जिससे दाम लगातार ऊपर नीचे होते हैं।
- **सर्राफा:** यह वह जगह है जहां आप फिजिकल सोना-चांदी खरीदते हैं। फिजिकल गोल्ड को लाने, ले जाने और स्टोर करने का खर्च इसमें जुड़ा होता है।

ज्वेलर्स से सोना खरीदते समय इन 2 बातों का रखें ध्यान

1. **सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें:** हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है।
2. **कीमत क्रॉस चेक करें:** सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज (जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट) से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होता है।

सर्राफा बाजार में चांदी ₹2.52 लाख प्रति किलो बिक रही

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिए-शन (IBJA) के अनुसार, आज सर्राफा बाजार में चांदी 30,230 रुपए गिरकर 2,52,232 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है।

सेंसेक्स में 500 अंक की गिरावट

मुंबई। शेयर बाजार में आज यानी 5 फरवरी को गिरावट है। सेंसेक्स 500 अंक गिरकर 83,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक की गिरावट है, ये 25,600 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। ऑटो, मेटल और फार्मा शेयर्स में बिकवाली है। वहीं IT और FMCG शेयर्स में तेजी दिखने को मिल रही है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 गिरकर कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 50 शेयरों में से 37 शेयर नीचे हैं। कल 4 फरवरी को सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 83,818 पर बंद हुआ। निफ्टी में 48 अंक की बढ़त रही, ये 25,776 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, एनर्जी और FMCG शेयर्स में बढ़त रही। वहीं IT और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में बढ़त रही। निफ्टी 50 शेयरों में से 38 चढ़कर बंद हुए। जापान का निक्केई इंडेक्स 0.73% गिरकर 53,898 पर और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 3.58% नीचे 5,179 पर कारोबार कर रहा है। हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग 1.28% नीचे 26,503 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.03% गिरकर 4,059 पर कारोबार कर रहा है।

पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी आज से शुरू होगी

ओला-उबर की तरह ड्राइवर को नहीं देना होगा कमीशन, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे लॉन्च

नई दिल्ली, एजेंसी

देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस 'भारत टैक्सी' आज लॉन्च की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे। इस नई सर्विस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और वे खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या मालिक होंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, 'भारत टैक्सी' का उद्देश्य ड्राइवरों को निजी एग्रीगेटर कंपनियों के मॉडल से आजादी दिलाना है। टैक्सी का ट्रायल 2 दिसंबर को दिल्ली और गुजरात के राजकोट में शुरू किया गया था, जो सफल रहा है। लॉन्चिंग के दौरान अमित शाह बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 ड्राइवर्स (जिन्हें 'सारथी' कहा गया है) को सम्मानित करेंगे। इन ड्राइवर्स को कंपनी के शेयर

सर्टिफिकेट भी बांटे जाएंगे। सम्मानित होने वाले ड्राइवर्स को 5 लाख रुपए का एक्सिडेंटल और 5 लाख रुपए का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले सभी ड्राइवर्स के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स और ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। भारत टैक्सी को अगले दो साल में देश के सभी राज्यों और प्रमुख शहरों में शुरू करने का टारगेट है। इसके लिए सरकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के साथ इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। दिल्ली के 7 प्रमुख स्थानों पर ड्राइवरों के लिए सपोर्ट सेंटर भी शुरू किए गए हैं।

जीरो कमीशन और सर्ज-प्राइसिंग से राहत मिलेगी

निजी कंपनियां जैसे ओला और उबर आमतौर पर ड्राइवरों की कमाई से 20% से 30% तक कमीशन वसूलती हैं। इसके उलट, भारत टैक्सी 'जीरो-कमीशन' मॉडल पर काम करेगी। यानी ड्राइवर जितनी कमाई करेगा, वह सीधे उसके पास जाएगी। इसके साथ ही, ग्राहकों के लिए भी राहत की बात यह है कि इसमें 'सर्ज-प्राइ-सिंग' (पीक ऑवर्स में ज्यादा किराया) का सिस्टम नहीं होगा। इससे यात्रियों को भी किफायती दरों पर टैक्सी मिल सकेगी।

यूपी में चाइनीज मांझे से मौत अब हत्या मानी जाएगी

योगी अफसरों पर भड़के, पूछा- बैन के बाद कैसे बिक रहा, एक साल में 8 मौतें

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। चाइनीज मांझे से हो रहीं मौतों पर सीएम योगी अफसरों पर भड़क गए। उन्होंने अफसरों से पूछा कि बैन के बाद भी बाजार में मांझा कैसे बिक रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा- अब चाइनीज मांझे से मौत होने को हत्या माना जाएगा। पुलिस प्रमुखों को जिलेवार छापेमारी करने के निर्देश दिए। दरअसल, बैन के बाद भी यूपी में धड़ल्ले से चाइनीज मांझे बिक करे। प्रदेश में बीते एक साल में 8 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को ही लखनऊ में MR का गला कट गया था। इनकी तड़प-तड़कर मौत हो गई थी। CM ने साफ किया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है। इसकी बिक्री और इस्तेमाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी ने पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि इस अवैध नेटवर्क की पहचान करें। तत्काल छापेमारी कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। यूपी में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बाद भी इसकी बिक्री हो रही है। भारत में सामान्य धागे से पतंग की डोर तैयार होती है, लेकिन चीन में नायलॉन के साथ मेटलिक पाउडर का उपयोग होता है। इसमें कांच और लोहे के चूरे को भी मिलाया जाता है ताकि धार और तेज हो।

योगी ने कहा- अब अगर चाइनीज मांझे से किसी की जान जाती है तो हत्या का केस दर्ज कर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। चाइनीज मांझे की जब्ती के लिए पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस सघनता से अभियान चलाएगी।

लखनऊ में चलती बाइक पर एमआर का गला कटा

4 फरवरी को लखनऊ में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने की वजह से एमआर की मौत हो गई थी। वह बाइक से जा रहे थे। तभी उनके गले में चाइनीज मांझा फंस गया। खून से लथपथ होकर वह बाइक समेत गिर गए और करीब 10 मिनट तक तड़पते रहे। राहगीरों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान मोहम्मद शोएब (33) के रूप में हुई। घटना दोपहर करीब 2 बजे की खाला बाजार थाना क्षेत्र के हैदरगंज ओवरब्रिज की है।

शोएब, मृतक

डॉक्टर की गर्दन कट गई थी, बीच सड़क तड़पकर मौत

14 जनवरी को जौनपुर में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। वह बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया और गर्दन कटती चली गई। मांझे की धार इतनी तेज थी कि उनकी गले की हड्डी तक कट गई थी। हादसा बुधवार दोपहर करीब 12 :30 बजे लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद चौराहे पर हुआ था। मृतक की पहचान केराकत निवासी डॉक्टर समीर हाशमी (28) के रूप में हुई थी।

एक साल में चाइनीज मांझे से 8 की जान गई

- **लखनऊ (11 दिसंबर 2025):** बाइक से अपने घर जा रहे युवक की गर्दन कट गई थी। डॉक्टरों ने गले में सात टांके लगाकर युवक की जान बचाई थी।
- **जौनपुर (10 दिसंबर 2025):** बेटे को स्कूल छोड़कर बाइक से लौट रहे कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप तिवारी की मौत हो गई थी। उनका गला कट गया था।
- **शाहजहांपुर (23 अक्टूबर 2025):** थाना कांट क्षेत्र के नगला जाजू निवासी 26 वर्षीय रवि शर्मा पत्नी के साथ ससुराल जा रहे थे। रोजा के हांडा पुल के पास चाइनीज मांझा गर्दन में लगा। मौके पर गंभीर चोट, अस्पताल में मौत हुई।
- **अलीगढ़ (30 सितंबर 2025):** 28 साल के सलमान स्कूटर से दुकान जा रहे थे। जमालपुर पुल पर चाइनीज मांझा गर्दन में उलझा, गहरा कट लगा। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
- **गोरखपुर (29 जुलाई 2025):** अमित गुप्ता मां के साथ बाइक से धर्मशाला जा रहे थे। सूरजकुंड पुल पर मांझा गर्दन में फंसा, 4 नसें कट गईं। हेलमेट होने के बावजूद गंभीर चोटें आईं। लंबा ऑपरेशन हुआ, जान बच गई।
- **शाहजहांपुर (11 जनवरी 2025):** ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल शाहरुख हसन चाइनीज मांझे की चपेट में आए। गर्दन पर तेज कट लगा, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

60 फीट ऊंचे पेड़ से लटकता मिला शव

हाइड्रोलिक प्लेटफार्म से उतारने में लगे 5 घंटे, युवक की पहचान नहीं हुई

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ के चारबाग इलाके में एक युवक ने 60 फीट ऊंचे पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। शव लटकता देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हाइड्रोलिक मशीन मंगाकर करीब 5 घंटे मशक्कत करके शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। पहचान नहीं होने के कारण शव को मॉर्च्युरी में रखवाया गया। पुलिस के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब 12 बजे नाका पुलिस को सूचना मिली एक अज्ञात युवक स्टेशन के पीछे की तरफ पेड़ से लटक गया है। इसके बाद टीम ने शव उतारने का प्रयास शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड और एसडी-आरएफ को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को नीचे उतारा।

- करीब 60 फीट की ऊंचाई पर शव लटकता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
- हाइड्रोलिक मशीन मंगाकर शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। पहचान नहीं होने के कारण शव को मॉर्च्युरी में रखवाया गया है।

फास्ट न्यूज

दिल्ली-वाराणसी इंडिगो उड़ान लखनऊ डायवर्ट

लखनऊ। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान को गुरुवार सुबह वाराणसी में खराब मौसम के कारण लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया। विमान लगभग 2 घंटे तक लखनऊ एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, जिससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, दिल्ली से सुबह 6 :30 बजे वाराणसी पहुंचने वाली इंडिगो की नॉन-शेड्यूल उड़ान (6ई 6741) को लखनऊ एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट किया गया।

कानपुर-सागर हाईवे पर 20 किमी लंबा जाम

कानपुर। कानपुर के बिधनू में आगे चल रहे ट्रक में पीछे से डंपर जा घुसा। हादसे के बाद कानपुर-सागर हाईवे पर जाम लगना शुरू हो गया। बिधनू पुलिस और एनएचआई ने क्षतिग्रस्त वाहन को हाइवे से किनारे नहीं कराया। इसके चलते लगभग 6 घंटे तक हाइवे पर यातायात प्रभावित रहा। जाम लगने की सूचना मिलते ही घाटमपुर एसीपी मौके पर पहुंचे उन्होंने पुलिस बल के साथ क्षतिग्रस्त वाहन को किनारे करवा कर हाईवे पर यातायात बहाल कराया है। इस दौरान लगभग 20 किलोमीटर तक जाम के हालात बने रहे। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे बिधनू थाना क्षेत्र के रिंद नदी पुल के पास आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी। इससे अनियंत्रित डंपर ट्रक में पीछे से जा घुसा। हादसे में डंपर चालक पतरेठा निवासी बब्लू और क्लीनर घनश्याम घायल हो गया।

भाई ने बहन के सिर में मारी गोली, मौत

आगरा। आगरा में भाई ने अपनी बहन के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। वह बिजली ठीक करने का बहाना बनाकर देर रात में दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगते ही महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी अपने दो दोस्तों के साथ फरार हो गया। बुधवार देर रात हुई यह वारदात शाहगंज थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर की है। आरोपी की पहचान हरि सिंह के रूप में हुई है।

यूपी में 2 साल में 1 लाख लोग लापता

लखनऊ हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को रिकॉर्ड सहित तलब किया

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों से जुड़े मामलों को लेकर गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने इस संबंध में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के संबंधित विभागों से विस्तृत आंकड़े और रिकॉर्ड तलब किए हैं। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने इस दौरान अपर मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और मामले की प्रगति से न्यायालय को अवगत कराएं। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने पारित किया। दरअसल, यह मामला चिनहट क्षेत्र निवासी विक्रमा प्रसाद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने न्यायालय को बताया था

कि उनका बेटा जुलाई 2024 में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था। इस संबंध में उन्होंने तत्काल चिनहट थाने में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। याची का आरोप है कि कई बार थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी उनके बेटे की तलाश के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए गए। पुलिस की लापरवाही से परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने न सिर्फ याची के बेटे की तलाश में की गई कार्रवाई का विवरण मांगा, बल्कि प्रदेशभर में गुमशुदा लोगों से संबंधित मामलों की स्थिति पर भी रिपोर्ट तलब की। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव (गृह) की ओर से एक शपथ पत्र दाखिल किया गया। शपथ पत्र में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश में कुल 1,08,300 लोगों के लापता होने की सूचनाएं पुलिस के पास दर्ज हुई हैं। इनमें बच्चों, महिलाओं और युवाओं की संख्या भी बड़ी बताई जा रही है।कोर्ट ने इन आंकड़ों को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से पूछा है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों के लापता होने के मामलों में अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

संबंधित अधिकारियों का कार्य संतोषजनक नहीं

शपथपत्र में यह भी बताया गया कि इन लापता व्यक्तियों में से मात्र 9,700 लोगों का ही पता चल सका है। न्यायालय ने इन आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि गुमशुदा लोगों के संबंध में संबंधित अधिकारियों का कार्य संतोषजनक नहीं है। न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर बताया और इसे प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में शीर्षक से जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया, जिसकी आज सुनवाई हुई।

युवा कल्याण अधिकारी पर दहेज उत्पीड़न की एफआईआर

पीड़िता बोली- शादी में ₹93 लाख, थार दी, अब ₹50 लाख, फॉर्चूनर भी मांग रहे

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में जिला कल्याण अधिकारी पर दहेज उत्पीड़न की FIR दर्ज की गई है। अधिकारी के खिलाफ उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। पुलिस को बताया है कि अधिकारी पति को शादी में 93 लाख और थार गाड़ी दी गई थी। उसके बाद वह और परिवार वाले हैं। पीड़िता निकिता तिवारी के अनुसार, 14 फरवरी 2025 को बीआर पैलेस, आईआ-ईएम रोड लखनऊ में हिंदू रीति-रिवाज से शिवाकांत द्विवेदी के साथ उसका विवाह हुआ था। शादी के बाद वह जानकीपुरम विस्तार स्थित ससुराल पहुंची, जहां पति शिवाकांत द्विवेदी और सास-ससुर ने कम दहेज का ताना देना शुरू कर दिया। निकिता का आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले 25 लाख रुपए नकद और

- शिवाकांत द्विवेदी जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी विभाग में कार्यरत हैं।

फॉर्च्यूनर कार की मांग की। कुछ समय बाद यह मांग बढ़ाकर 50 लाख रुपए नकद और नई फॉर्च्यूनर कर दी गई। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई और बार-बार अपमानित किया गया। पीड़िता ने तहरीर में बताया कि पति शिवाकांत द्विवेदी का मृदाली पांडे नाम की महिला से अवैध संबंध है। आरोप है कि दोनों साथ-साथ कई जगह घूमे और होटलों में भी रुके। जब इस बारे में सवाल किया गया तो पति और ससुराल पक्ष ने हिंसक व्यवहार किया और धमकियां दीं। तहरीर के मुताबिक, एक विवाद के दौरान पति ने निकिता का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। सास और ननद द्वारा मारपीट करने और ससुर द्वारा गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता का कहना है कि उसे साफ तौर पर धमकी दी गई कि अगर मांगें पूरी नहीं की गईं तो उसे छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर ली जाएगी। निकिता का कहना है कि ससुराल वालों ने उसके सभी आभूषण अपने पास रख लिए और उसे केवल चांदी की बिछिया और पायल पहनने को दी।

समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज की

प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने सभी फार्म-7 को निरस्त करने और त्वरित कार्रवाई की मांग की

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्री श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में गड़बड़ी और साजिश की शिकायत की है। ज्ञापन में कहा गया है कि फतेहपुर, मथुरा, मऊ, अमेठी, जौनपुर, बस्ती, भदोही, बलरामपुर (तुलसीपुर), संभल (असमौली), जालौन, कासगंज, मऊ, सम्भल और गोण्डा (गौरा) सहित लगभग सभी विधान सभाओं में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाने के प्रयास में हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने फार्म-7 में मतदाता का नाम और ई-पिक

नम्बर प्रिंट करवा कर बी0एल0ओ0 और ई0आर0ओ0 के पास जमा कर दिया है। इसके अलावा, जिलाधिकारी और ई0आर0ओ0 पर दबाव डालकर सपा समर्थक मतदाताओं के नाम हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। सपा ने कहा है कि यह प्रयास वैध मतदाताओं के अधिकारों के खिलाफ है और इसके लिए कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। फतेहपुर जिले के खागा विधानसभा के पोलिंग बूथ संख्या 335 पर मतदाता क्रमांक 46, 107, 344, 296, 392, 297, 389, 120, 62, 368 पर शकील अहमद, सैदुन निशा, तौशीफ अहमद, मो0 हनीफ, निदा फातिमा, महमूदा बानो, आशमा, नुसरत जहाँ, कनीज, इशराह अहमद जैसे समाजवादी समर्थक पी0डी0ए0 और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। भाजपा समर्थक सूर्य प्रकाश द्वारा फार्म-7 भरकर इनके नाम हटवाने का प्रयास किया गया। मथुरा की माँट विधानसभा के पोलिंग बूथ संख्या 93, 110, 111, 112 पर 400 से अधिक फार्म-7 जमा किए गए हैं। इसके अलावा बल्देव विधानसभा के पोलिंग बूथ 178, 180, 181, 400, 401, 402 पर बड़ी संख्या में फार्म-7 जमा कराए गए। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा के पोलिंग बूथ 209 और 211 में भी भाजपा पदाधिकारियों द्वारा समाजवादी समर्थक मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई।

घटना : जालौन में 500 मीटर तक दौड़ाकर 50 लोगों को काटा, तीन बेहोश हुए

मधुमक्खियों के हमले से जलती चिता छोड़ भागे लोग

तमसा संकेत, एजेंसी

जालौन जिले के महमूद नगर डाले का पुरवा बड़ा गांव एक भयावह घटना का गवाह बना। गाँव के बुजुर्ग वीर सिंह (78) का निधन होने के बाद गुरुवार दोपहर अंतिम संस्कार के लिए उनका शव श्मशान घाट ले जाया गया। लेकिन इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और अंतिम संस्कार स्थगित हो गया। घटना के समय श्मशान घाट पर आसपास के लगभग 50 ग्रामीण मौजूद थे। जैसे ही मधुमक्खियों ने हमला किया, लोग जलती चिता छोड़कर भागे। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों और जमीन पर गिर गए। इस हमले में चंद्रशेखर उर्फ चंदू, धीरू, नेता, देवी चरण, विजय शर्मा सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तीन लोग बेहोश हो गए, जबकि अन्य को गंभीर चोटें आई। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी आंखों, हाथों और शरीर के

अन्य हिस्सों में डंक मारे जाने से गंभीर सूजन आ गई। घायलों को तुरंत कदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। कई ग्रामीणों ने अपने स्तर पर भी प्राथमिक उपचार किया। ग्रामीणों का कहना है कि घटना ने गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कोई भी अंतिम संस्कार स्थल पर वापस नहीं लौटना चाहता। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक वीर सिंह के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पर चिता जलाते समय मधुमक्खियों का झुंड अचानक सक्रिय हो गया। हमले की वजह से लोग अफरा-तफरी में भागते हुए दूर जाकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करने लगे। इस कारण मृतक की अंतिम विदाई भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। घटना के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति का जायजा लिया। कदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी घायलों का उपचार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि श्मशान घाट और आसपास के क्षेत्रों में मधुमक्खियों की निगरानी और नियंत्रण के उपाय किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। स्थानीय लोग भयावह घटना को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते मधुमक्खियों के झुंड को नियंत्रित करने के उपाय किए गए होते, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल नहीं होते। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि वे घायलों की देखभाल सुनिश्चित करें और श्मशान घाट में सुरक्षा के विशेष इंतजाम करें।

घटना की सूचना बीडीओ संदीप मिश्रा को दी गई, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते चिकित्सा टीम मौके पर पहुंच जाती तो घायलों को राहत मिल सकती थी।

पृष्ठ 01 का शेष...

कांग्रेस के वक्त ...

हमने 2014 के बाद नीति आयोग बनाया। PM मोदी ने कहा- देश के कई जिलों को पिछड़ा मानकर छोड़ दिया था और जो पिछड़े इलाके थे उनकी हालत और खराब कर दी गई थी। हमने स्थिति को बदला पूरे देश में आज छत्तीसगढ़ का बस्तर ओलंपिक के नाम से चर्चा में है। कांग्रेस के हमारे साथियों को इंम्पलीमेंटेशन नजर नहीं आता। PM ने कहा कि ये लोग कितनी गलत बातें फैलाते थे। ये लोग अर्बन नक्सल की तरह लोगों कंपनी के बाहर मजदूरों को भड़काते थे। जब उनकी सरकार थे तब इनसे संभाला नहीं गया। हमने पीएसयू में भी रिफॉर्म किए, आज एलआईसी बेस्ट परफार्मेंस कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा- जिन पीएसयू को कांग्रेस ताले लगवाने वाली थी आज पीएसयू रिकॉर्ड प्रॉफिट पर हैं। वे मेक इन इंडिया को भी गति दे रहे हैं, रोजगार बना रहे हैं विश्व के साथ जुड़ रहे हैं। पीएसयू को देश और विदेश से बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने विश्वासघात करने में किसानों को भी नहीं छोड़ा।

मेघालय में अवैध ...

जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए शिलांग के अस्पताल में रैफर किया गया। पुलिस के मुताबिक विस्फोट कोयला खनन के दौरान हुआ और यह खदान अवैध रूप से चल रही थी। धमाके का कारण के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने साल 2014 में मेघालय में रैट-होल कोयला खनन और अन्य अवैज्ञानिक खनन तरीकों पर रोक लगा दी थी। यह रोक पर्यावरण को होने वाले नुकसान और मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए लगाई गई थी। साथ ही, ऐसे तरीकों से निकाले गए कोयले के अवैध परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। रैट-होल माइनिंग में बहुत संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं, जिनकी ऊंचाई आमतौर पर 3-4 फीट होती है।

यूपीएससी-सेवा ...

तो उम्मीदवार को सिर्फ एक बार यानी सीएसई-2027 में रैंक सुधारने का मौका मिलेगा। मौका तभी मिलेगा जब उम्मीदवार को ट्रेनिंग जॉइन न करने की वन टाइम एक्जेम्शन (एक बार की छूट) मिले। छूट फाउंडेशन कोर्स तक सीमित होगी। यदि उम्मीदवार न ट्रेनिंग जॉइन करता है, और न छूट लेता है, तो सीएसई-2026 और सीएसई-2027 दोनों के आधार पर मिली सेवा अपने आप रद्द हो जाएगी। सीएसई 2026 से चयनित उम्मीदवार सीएसई 2027 देना चाहते हैं, तो अनुमति जरूरी होगी। सीएसई 2028 या उसके बाद परीक्षा देने के लिए इस्तीफा अनिवार्य होगा। 2025 में करीब 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स ने एप्लिकेशन भरा था। जिनमें से 14,161 एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स पास कर मेन्स तक पहुंचे। 2,736 को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जबकि 979 पदों के लिए फाइनल सिलेक्शन हुआ। इससे पहले 2024 मे लगभग 13 लाख से ज्यादा आवेदन आए और करीब 5.8 लाख प्रीलिम्स में शामिल हुए। 1,009 पदों पर सिलेक्शन हुआ। इसी तरह 2023 में करीब 13 लाख एप्लिकेशन आए और 1016 पदों पर फाइनल सिलेक्शन हुआ। लोकसभा में बुधवार को पूछा गया कि क्या लद्दाख के उम्मीदवारों को सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में भारतीय भाषा के क्वालिफाइंग पेपर (पेपर-A) से छूट देने का कोई प्रस्ताव है। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जबाव दिया कि सिविल सेवा परीक्षा के नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए बराबरी का मौका देने के लिए सरकार सुधार और जरूरी कदम उठाती रहती है। फिलहाल लद्दाख के उम्मीदवारों को भाषा पेपर से छूट देने का कोई तय फैसला घोषित नहीं किया गया है। मौजूदा नियम CSE रूल्स-2025) के तहत 6 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के उम्मीदवारों के लिए भारतीय भाषा का पेपर देना अनिवार्य नहीं है।

लखनऊ से गुरु

सेवा, समर्पण और मानव कल्याण की भावना से प्रेरित यह पहल सबका स्वास्थ्य, सबका सम्मान के संकल्प को सशक्त करती है। उन्होंने इस पुनीत प्रयास से जुड़े सभी चिकित्सकों, आयोजकों एवं स्वयंसेवकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दीं।

'लापता लेडीज' ...

पुलिस ने बताया कि कई मामलों में स्वेच्छा से घर छोड़ने या भाग जाने वाले व्यक्तियों की वापसी की सूचना या तो नहीं दी जाती है या बहुत देर से दी जाती है। नाबालिगों के भाग जाने के मामलों में उनकी वापसी की सूचना 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही दी जाती है।

भारत-अमेरिका ...

यह नेगोशिएशंस पिछले साल फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका विजिट से शुरू हुए थे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने डील की घोषणा की थी। भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद किया है और वेनेजुएला जैसे अल्टरनेटिव मार्केट देख रहा है। गोयल ने कहा कि यह भारत-अमेरिका रिलेशंस को मजबूत करने का अहम स्टेप है और विकसित भारत 2047 की यात्रा में मदद करेगा। जॉइंट स्टेटमेंट के बाद लीगल एग्रीमेंट पर काम तेज होगा। मिड-मार्च तक पहला ट्रांच का फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हो सकता है।

यूपी पीसीएस 2024 मेंस का रिजल्ट घोषित

2719 अभ्यर्थी हुए पास, अब इंटरव्यू देंगे, कुल पद 947 हैं

तमसा संकेत, एजेंसी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने यूपी पीएससी-2024 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कुल 2719 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब ये छात्र इंटरव्यू देंगे। कुल 24 प्रकार के पदों के लिए 947 की भर्ती होगी। बता दें कि मुख्य परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच आयोजित की गई थी। इसके लिए लखनऊ और प्रयागराज में सेंटर बनाए गए थे। PCS 2024 प्री के लिए कुल 5,76,154 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 2,43,111 अभ्यर्थी पहले सत्र में, जबकि 2,41,359 अभ्यर्थी दूसरे सत्र में शामिल हुए थे। प्री का रिजल्ट मार्च 2025 में जारी किया गया था। इसमें से 15,066 अभ्यर्थियों ने मेन्स के लिए क्वालीफाई किया था। मेन्स परीक्षा में 13776 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पीसीएस 2024

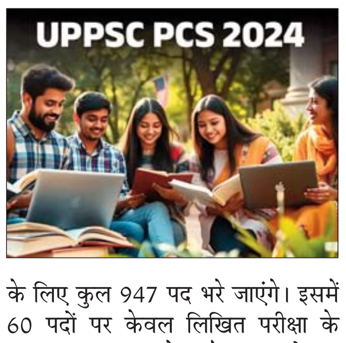

के लिए कुल 947 पद भरे जाएंगे। इसमें 60 पदों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होना है। इन पदों का परिणाम अंतिम चरण परिणाम के साथ घोषित किया जाएगा। 60 रिक्तियों को छोड़कर 887 रिक्तियों पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होना है। इंटरव्यू के लिए अलग से सूचना दी जाएगी। यह जानकारी यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने दी है। इस परीक्षा से संबंधित कुल 15 याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकिाशत लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676